



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-01072024-255057  
CG-MH-E-01072024-255057

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]  
No. 452]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 28, 2024/आषाढ 7, 1946  
NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 28, 2024/ASHADHA 7, 1946

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया

(मानव सम्पदा विभाग)

अधिसूचना

मुम्बई, 28 जून, 2024

**क्रमांक 290 (अ).**—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 की उप-धारा (2) के खंड (एफ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया का निदेशक मंडल, भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श के पश्चात तथा केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी सहित, एतद्वारा सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 में संशोधन हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है: -

## 1. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ-

- (1) इन विनियमों को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकता है.
- (2) ये विनियम, राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे .

2. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 1995 (इसके पश्चात उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में, विनियम 2 में, खंड (एस) में, उप-खंड (डी) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:

“इसके अतिरिक्त कि दिनांक 1 नवम्बर, 2012 से लागू विशेष भत्ते को इससे पृथक रखा जाएगा:

बशर्ते कि एक कर्मचारी जो दिनांक 1 नवंबर, 2017 को बैंक की सेवाओं में था एवं जिसकी स्टेगनेशन वेतन वृद्धि को उनके अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने की तारीख से संशोधित आवधिकता के अनुसार पुनः समायोजित किया गया है, पेंशन के प्रयोजनों के लिए दिनांक 1 नवंबर, 2017 से इस तरह के संशोधित स्टेगनेशन वेतन वृद्धि के लिए सांकेतिक रूप से पात्र होगा, परंतु इस तरह के पुनः समायोजन के कारण मौद्रिक लाभ केवल दिनांक 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा।”

3. उक्त विनियमों के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) में, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया जाएगा, अर्थात्

-

“बशर्ते कि किसी कर्मचारी, जो बैंक की सेवा में स्थायी आधार पर पूर्णकालिक कार्य पर अथवा वेतनमान अनुसार स्थायी रूप से अंशकालिक आधार पर कार्यरत है, को हटाने हेतु उसकी पूरी पिछली सेवा को जब्त करने की आवश्यकता नहीं होगी तथा पेंशन सम्बंधी लाभों के लिए पात्र होगा।”

4. उक्त विनियमों के विनियम 36 में, खंड (एफ) के बाद, निम्नलिखित खंड डाला जाएगा, अर्थात्:

“(जी) अंशकालिक कर्मचारी के अलावा, किसी कर्मचारी हेतु तीन हजार नौ सौ पचासी रुपये प्रति माह, जहां कर्मचारी 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो, एक हजार तीन सौ पैंतीस रुपये प्रति माह 1/3 वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी हेतु, दो हजार रुपये प्रति माह, 1/2 वेतन पाने वाले अंशकालिक कर्मचारी हेतु तीन हजार रुपये प्रति माह- 3/4 वेतन प्राप्त करने वाला अंशकालिक कर्मचारी, जहां अंशकालिक कर्मचारी 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुआ हो।

5. उक्त विनियमों के विनियम 40 में,

(ए) उप-विनियम (1) में, -

(i) खंड (बी) में, पहले प्रावधान के लिए, निम्नलिखित प्रावधान को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“बशर्ते कि बेटे या बेटी (विधवा या तलाकशुदा सहित) को देय पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी जब पात्र बेटा या बेटी सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार या स्व-रोजगार के माध्यम से प्रति माह बारह हजार रुपये से अधिक की राशि अर्जित करना शुरू कर दें”;

(ii) खंड (सी) के लिए, निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

“(सी) माता-पिता के मामले में, पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाएगी या स्वीकार्य नहीं होगी यदि माता-पिता में से किसी एक की आय या माता-पिता की कुल आय सरकारी या निजी क्षेत्र में रोजगार या स्व-रोजगार के द्वारा रुपये बारह हजार प्रति माह से अधिक हो;”;

(बी) उप-विनियम (4) में, -

(i) खंड (ए) में, उपखंड (vi) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

“(vii) छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपये प्रति माह केवल उन कर्मचारियों, अधिकारियों और श्रमिकों के संबंध में, जो दिनांक 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या जिनकी मृत्यु हो गई:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप-खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं होंगे और उपरोक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि विनियम 39 के उप-विनियम (3) के खंड (ए) के उप-खंड (i) और खंड (बी) के उप-खंड (i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी।

(ii) खंड (बी) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: - (ii) खंड (बी) में, उप-खंड (vi) के बाद, निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्: :—

"(vii) छब्बीस हजार पांच सौ साठ रुपये प्रति माह केवल उन कर्मचारियों, अधिकारियों और श्रमिकों के संबंध में, जो दिनांक 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या जिनकी मृत्यु हो गई:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं होगा और उपरोक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि जैसा भी मामला हो, विनियम 39 का उप-विनियम (1) या खंड (ए) का उप-खंड (i) और उप-विनियम (3) के खंड (बी) का उप-खंड(i) के प्रावधानों के अनुसार देय होगी.

(iii) खंड में (सी), उप खंड-vi) के बाद, निम्नलिखित उपखंड डाले जाएंगे-, अर्थात्- :

"(vii) तेरह हजार दो सौ अस्सी केवल उन कार्मिकों, दोनों अधिकारी और कर्मचारी हेतु जो दिनांक 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए या जिनका निधन हो गया:

बशर्ते कि 1 अप्रैल, 2021 से उप खंड (i) से (vii) प्रभावी नहीं होगा और उपरोक्त सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए दोनों पेंशन की राशि प्रावधानों के अनुसार विनियम 39 का उप-विनियम (1)" देय होगी.

6. उक्त विनियम के परिशिष्ट -II में, खंड )4) के स्थान पर, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:

"(4) 1 मई, 2005 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो, तिमाही में 2288 अंकों से अधिक के प्रत्येक 4 अंकों में से श्रृंखला 1960 =100 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत, प्रत्येक उक्त 4 अंक के लिए महंगाई राहत में कमी या वृद्धि की गणना मूल पेंशन के 0.18 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

बशर्ते कि 1 मई, 2005 को और उसके बाद से, उन कर्मचारियों के संबंध में, जो 1 नवंबर, 2002 को या उसके बाद, लेकिन 30 अप्रैल, 2005 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए थे, महंगाई राहत इस खंड के अनुसार देय होगी.

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2007 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो, तिमाही में 2836 अंकों से अधिक के प्रत्येक 4 अंकों में से श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत, प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में कमी की ऐसी वृद्धि की गणना मूल पेंशन के 0.15 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2012 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो, प्रत्येक 4 अंकों में से 4440 अंक से अधिक 1960=100 श्रृंखला में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य

सूचकांक का तिमाही औसत, प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.10 प्रतिशत की दर से की जाएगी:

बशर्ते कि 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के संबंध में, महंगाई राहत प्रत्येक वृद्धि के लिए देय होगी या प्रत्येक गिरावट के लिए वसूली योग्य होगी, जैसा भी मामला हो, 6352 अंकों में से प्रत्येक 4 अंकों में से श्रृंखला 1960=100 में औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का तिमाही औसत, प्रत्येक उक्त 4 अंकों के लिए महंगाई राहत में ऐसी वृद्धि या कमी की गणना मूल पेंशन के 0.07 प्रतिशत की दर से की जाएगी

7. उक्त विनियमों के परिशिष्ट III में, खंड )एफके बाद (, निम्नलिखित खंड डाले जाएंगे, अर्थात्- :
- " (जी) 1 नवंबर, 2017 को या उसके बाद सेवानिवृत्त होने वाले अंशकालिक कर्मचारियों के अलावा अन्य कार्मिकों (अधिकारी और कर्मचारी दोनों) हेतु

मासिक वेतनमान	मासिक पारिवारिक पेंशन की राशि
(1)	(2)
₹15,880 तक	वेतन का 30% मूल पारिवारिक पेंशन होगी एवं अतिरिक्त 30% भत्ता, जिसकी भविष्य निधि में योगदान हेतु गणना की जाती हो, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, यह अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी:  बशर्ते कि कुल मिलाकर मूल एवं अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन न्यूनतम ₹ 3985 प्रति माह होगी.
₹15,881 से ₹31,760	वेतन का 20% मूल पारिवारिक पेंशन होगी एवं अतिरिक्त 20% भत्ता, जिसकी भविष्य निधि में योगदान हेतु गणना की जाती हो, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, यह अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी:  बशर्ते कि कुल मिलाकर मूल एवं अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन न्यूनतम ₹ 4900 प्रति माह होगी.
₹ 31,760 से अधिक	वेतन का 15% मूल पारिवारिक पेंशन होगी एवं अतिरिक्त 15% भत्ता, जिसकी भविष्य निधि में योगदान हेतु गणना की जाती हो, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, यह अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी:  बशर्ते कि कुल मिलाकर मूल एवं अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन न्यूनतम ₹ 6365 प्रति माह एवं अधिकतम ₹ 13280 प्रति माह होगी.

(एच) दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से खंड (ए) से (जी) प्रभावी नहीं होंगे और उक्त खंडों में उल्लिखित सभी कार्मिकों (अधिकारी एवं कर्मचारियों दोनों) के संबंध में, वेतन का 30% मूल पारिवारिक पेंशन होगी एवं अतिरिक्त 30% भत्ता, जिसकी भविष्य निधि में योगदान हेतु गणना की जाती हो, लेकिन महंगाई भत्ते के लिए नहीं, यह अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन होगी .".

### विवरणात्मक ज्ञापन

जिन विनियमों को पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, वे इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ एवं बैंकों के शीर्ष स्तरीय कर्मचारी एवं अधिकारी सघों के बीच हस्ताक्षरित समझौतों, संयुक्त ज्ञापनों के सहमत नियमों और शर्तों के अनुसार हैं। इसलिए, ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पाँपी शर्मा, महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./221/2024-25]

**नोट:** मुख्य विनियम भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या सीओ/पीआरएस/पेंशन/95-96/278, दिनांक 29\* सितंबर, 1995 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम रूप से अधिसूचना संख्या 395(ई), दिनांक 1 सितंबर, 2023 द्वारा संशोधित किये गए।

### CENTRAL BANK OF INDIA

(Human Resources Department)

### NOTIFICATION

Mumbai, the 28th June, 2024

**No. 290(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (2) of section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Central Bank of India, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following regulations further to amend the Central Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995, namely:—

#### 1. Short title and commencement-

(1) These regulations may be called the Central Bank of India (Employees') Pension (Amendment) Regulations, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette

#### 2. In the Central Bank of India (Employees') Pension Regulations, 1995 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 2, in clause (s), in sub-clause (d), the following provisos shall be inserted, namely: -

"Provided further that special allowance introduced with effect from the 1st day of November, 2012 shall be excluded:

Provided further that an employee who was in the services of the Bank as on the 1st November, 2017 and whose stagnation increments have been re-adjusted as per revised periodicity from the date of reaching their maximum scale of pay shall be notionally eligible for such revised stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 for the purposes of Pension but the monetary benefit on account of such re-adjustment shall be payable only with effect from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later."

#### 3. In regulation 22 of the said regulations, in sub-regulation (1), the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that the removal of an employee, who is employed in the service of the Bank as a workman on full time work on permanent basis or on part-time work on permanent basis on scale wages, shall not entail for forfeiture of his entire past service and shall qualify for pensionary benefits."

#### 4. In regulation 36 of the said regulations, after clause (f), the following clause shall be inserted, namely: —

"(g) rupees three thousand nine hundred and eighty-five per month in respect of an employee, other than a part-time employee, where the employee retired on or after the 1st day of November, 2017, rupees one thousand three hundred and thirty-five per month in respect of a part-time employee drawing 1/3 scale of wages, rupees two thousand per month in respect of part-time employee drawing 1/2 scale wages, and rupees three thousand per month in respect of a part-time employee drawing 3/4 scale wages, where the part-time employee retired on or after the 1st day of November, 2017."

#### 5. In regulation 40 of the said regulations, -

a) in sub-regulation (1), —

i. in clause (b), for the first proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

"Provided that the family pension payable to son or daughter (including widowed or divorced) shall be discontinued or not be admissible when the eligible son or daughter starts earning a sum in excess of rupees twelve thousand per month from employment in Government or private sector or self-employment:";

ii. for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) in the case of parents, the family pension shall be discontinued or not be admissible if the income of one of the parents or the aggregate income of both the parents from employment in Government or Private sector or self-employment, exceeds rupees twelve thousand per month;";

b) in sub-regulation (4),-

i. in clause (a), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017.

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub-clauses (i) to (vii) shall cease to have effect and amount of both pensions for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 39.”;

ii. in clause (b), after sub-clause (vi), the following shall be inserted, namely:—

“(vii) twenty-six thousand five hundred and sixty rupees per mensem only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of both the pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub regulation (1) of regulation 39 or sub-clause (i) of clause (a) and sub-clause (i) of clause (b) of sub-regulation (3) of the said regulation, as the case may be.”;

iii. in clause (c), after the sub-clause (vi), following sub-clauses shall be inserted, namely: —

"(vii) thirteen thousand two hundred and eighty only in respect of employees, both officers and workmen, who retired or died on or after the 1st day of November, 2017:

Provided that on and from the 1st day of April, 2021, sub clause (i) to (vii) shall cease to have effect and the amount of the two pension for all the above said category of employees shall be payable as per the provisions of sub-regulation (1) of regulation 39.”.

6. In Appendix-II to the said regulations, for clause (4) in the Appendix-II shall be substituted, namely:-

"(4) In respect of employees who retire on or after the 1st May, 2005, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.18 per cent. of basic pension:

Provided further that on and from the 1st day of May, 2005, in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2002 but on or before the 30th day of April, 2005, dearness relief shall be payable in terms of this clause:

Provided that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2007, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 2836 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.15 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2012, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 4440 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.10 per cent. of basic pension:

Provided also that in respect of employees who retired on or after the 1st day of November, 2017, dearness relief shall be payable for every rise or be recoverable for every fall, as the case may be, of every 4 points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Consumer Price Index for Industrial Workers in the series 1960=100. Such increase or decrease in dearness relief for every said 4 points shall be calculated at the rate of 0.07 per cent. of basic pension."

7. In Appendix III to the said regulations, after clause (f), the following clauses shall be inserted, namely:—

"(g) in respect of employees (both officers and workmen) other than part-time employees retiring on or after the 1st day of November, 2017:

<b>Scale of pay per month</b>	<b>Amount of monthly family pension</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
Upto Rs. 15,880	30 per cent of the pay shall be the basic family pension and additional 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension:  Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.3985 per month.
Rs. 15,881 to Rs. 31,760	20 per cent of the pay shall be basic family pension and additional 20 per cent of allowance, which are counted for making contributions to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension:  Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to minimum of Rs.4900 per month.
Above Rs. 31,760	15 per cent. of the pay shall be the basic family pension and additional 15 per cent of allowances which are counted for making contributions to provident fund but not for the dearness allowance, shall be the additional family pension:  Provided that the aggregate of basic and additional family pension shall be subject to a minimum of Rs.6365 per month and maximum of Rs.13280 per month."

(h) On and from the 1st day of April, 2021 clauses (a) to (g) shall cease to have effect and in respect of all employees (both officers and workmen) mentioned in the said clauses, 30 per cent of the 'Pay' shall be the basic family pension plus 30 per cent of allowance which are counted for making contribution to provident fund but not for dearness allowance, shall be the additional family pension."

**Explanatory Memorandum**

The regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the settlements and Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level workmen unions and officers' associations of the banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.

POPPY SHARMA, General Manager-Hcm

[ADVT.-III/4/Exty./221/2024-25]

**Note:** The principal regulations were published in the Gazette of India, Part III, Section 4 vide notification number CO/PRS/PENSION/95-96/278, dated the 29th September, 1995 and lastly amended vide notification number 395(E), dated the 1st September, 2023.